Test Cloud

# Daily करेंट अफेयर्स

## 10 जुलाई 2025

## NATIONAL AFFAIRS

### 1. MIB ने AI-संचालित बहुभाषी सामग्री निर्माण को सक्षम करने के लिए WaveX के माध्यम से 'कला सेतु' लॉन्च किया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने अपने WaveX स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से "कला सेतु - भारत के लिए रीयल-टाइम लैंग्वेज टेक" चैलेंज शुरू किया है। यह पहल भारतीय AI स्टार्टअप्स को ऐसे स्केलेबल, स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है जो पाठ्य सूचना को कई भारतीय भाषाओं में वीडियो, ग्राफिक्स और ऑडियो प्रारूपों में परिवर्तित कर सकें।

**• इस चुनौती के तहत, भाग लेने वाले स्टार्टअप ऐसे उपकरण विकसित करेंगे जो टेक्स्ट को वीडियो व्याख्याकारों (text-to-video explainers) में बदल सकें, जिनमें विज़ुअल और बोलने की शैली को कस्टमाइज़ किया जा सके; टेक्स्ट को ग्राफिक्स (text-to-graphics) में बदलने वाले टूल जो गतिशील इन्फोग्राफिक्स बना सकें; और टेक्स्ट को ऑडियो (text-to-audio) में बदलने वाले सिस्टम, जो क्षेत्रीय उच्चारणों को दर्शाने वाली अभिव्यंजक आवाज़ों का उपयोग करें।**

**• प्रत्येक समाधान को किसानों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विविध दर्शकों के लिए आधिकारिक संचार को अधिक समावेशी और आकर्षक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**

**• कला सेतु का लक्ष्य सार्वजनिक संचार निकायों - जैसे ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और प्रेस सूचना ब्यूरो - को वास्तविक समय में घोषणाओं, अलर्ट और शैक्षिक सामग्री को स्थानीयकृत, मल्टीमीडिया प्रारूपों में स्वचालित रूप से परिवर्तित करने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे डिजिटल भाषा के अंतर को पाटा जा सके।**

**Key Points:-**

(i) स्टार्टअप 30 जुलाई 2025 तक आधिकारिक WaveX पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और एक कार्यशील न्यूनतम व्यवहार्य अवधारणा (MVC) डेमो वीडियो प्रस्तुत कर सकते हैं। चयनित टीमें नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुति देंगी, जहाँ विजेताओं को वेवएक्स इनोवेशन प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत समझौता ज्ञापन, पायलट परिनियोजन के अवसर और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) कला सेतु पहले की भाषा सेतु वास्तविक समय अनुवाद चुनौती (30 जून को शुरू की गई और 22 जुलाई तक खुली) का पूरक है, जो भविष्य के लिए तैयार, बहुभाषी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है जो समावेशी ई-गवर्नेंस के लिए अत्याधुनिक AI का लाभ उठाता है।

### 2. तमिलनाडु सरकार, HMIL और IIT मद्रास ने चेन्नई में हुंडई HTWO इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ करने के लिए हाथ मिलाया।

जुलाई 2025 की शुरुआत में, तमिलनाडु सरकार, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) ने आधिकारिक तौर पर हुंडई HTWO इनोवेशन सेंटर की योजना का अनावरण किया - जो चेन्नई के थाईयूर में एक अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र है, जो उद्योग और गतिशीलता में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।

**• IIT मद्रास डिस्कवरी सैटेलाइट कैम्पस में 65,000 वर्ग फुट में फैले इस केंद्र को HMIL और इसकी CSR शाखा, हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन से 100 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त है।**

**• तमिलनाडु का मार्गदर्शन कार्यालय और राज्य सरकार भी इस परियोजना का समर्थन कर रहे हैं, जिसके 2026 तक चालू होने का अनुमान है।**

**Key Points:-**

(i) इस केंद्र में इलेक्ट्रोलाइज़र और ईंधन सेल विकास, डिजिटल ट्विन सिमुलेशन, कस्टम टेस्ट रिग और कंटेनरीकृत पायलट डेमोंस्ट्रेटर पर केंद्रित उन्नत कम्प्यूटेशनल और प्रायोगिक प्रयोगशालाएँ होंगी। इसका उद्देश्य गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए स्केलेबल, स्वदेशी हाइड्रोजन समाधानों को उत्प्रेरित करना है।

(ii) तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा, HMIL के MD उन्सूकीम और IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह केंद्र मेक इन इंडिया पहल को रेखांकित करता है, अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में तमिलनाडु की भूमिका का समर्थन करता है और भारत के हाइड्रोजन कार्यबल का पोषण करते हुए 2070 तक नेट-जीरो और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता के देश के लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।

## 3. CEA ने नवीकरणीय ऊर्जा स्थलों में स्वचालित मौसम स्टेशनों के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश जारी किए हैं।

8 जुलाई, 2025 को, विद्युत मंत्रालय (MoP) के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने सौर और पवन ऊर्जा परियोजना स्थलों पर स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) की स्थापना हेतु नए तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए। इस कदम का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पूर्वानुमान, ग्रिड विश्वसनीयता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मौसम संबंधी आंकड़ों के संग्रह की सटीकता में सुधार करना है।

**• दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि 50 मेगावाट (MW) या उससे अधिक क्षमता वाली सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अपनी साइट पर कम से कम एक AWS स्थापित करना होगा। यह शर्त सौर और पवन ऊर्जा दोनों प्रतिष्ठानों पर लागू होती है ताकि कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए**

**आवश्यक निरंतर मौसम डेटा निगरानी सुनिश्चित की जा सके।**

**• AWS इकाइयों को 15 मिनट के अंतराल पर हवा की गति, तापमान, आर्द्रता और सौर विकिरण जैसे मौसम संबंधी मापदंडों को रिकॉर्ड करना होगा। इन आंकड़ों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाना चाहिए और वास्तविक समय के पूर्वानुमान और ग्रिड प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्रों को प्रेषित किया जाना चाहिए।**

**• CEA के अनुसार, सिंक्रनाइज़ ग्रिड संचालन की सुविधा के लिए AWS डेटा को राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (NLDC), क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (RLDC), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (REMCs) के बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।**

**Key Points:-**

(i) सभी AWS प्रणालियों को समय-समकालिक डेटा लॉगिंग सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) रिसीवर से लैस होना चाहिए। इससे बेहतर मौसम पूर्वानुमान मॉडल और ग्रिड विश्लेषण के लिए डेटा बिंदुओं की सटीक ट्रैकिंग और टाइमस्टैम्पिंग संभव हो पाती है।

(ii) खराब मौसम की स्थिति में भी निरंतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, AWS में सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी प्रणाली होनी चाहिए जो बिना किसी बाहरी बिजली आपूर्ति के बादल या कोहरे की स्थिति में कम से कम 20 दिनों तक काम कर सके। यह लचीलापन प्रतिकूल मौसम में भी निर्बाध निगरानी बनाए रखने में मदद करेगा।

(iii) यह पहल भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अंतर्गत ग्रिड आधुनिकीकरण और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। यह ऊर्जा स्थलों पर प्रणाली स्थिरता और साइबर सुरक्षा लचीलापन बनाए रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा एकीकरण को बढ़ाने के राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करती है।

## 4. गुजरात क्रूज़ भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया, जिसका उद्देश्य समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना है।

जुलाई 2025 की शुरुआत में, गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया, जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल, क्रूज़ भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ गया। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य गुजरात को अपनी विस्तृत तटरेखा का लाभ उठाकर एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी समुद्री पर्यटन स्थल में बदलना है।

**• गुजरात का परिदृश्य क्रूज़ पर्यटन के लिए अद्वितीय रूप से अनुकूल है, जहाँ 2,340 किलोमीटर लंबा समुद्र तट और साबरमती व नर्मदा जैसी नौगम्य नदियाँ बहती हैं। राज्य सरकार ने तीन प्रमुख क्रूज़ सर्किटों की पहचान की है—पडाला द्वीप-कच्छ का रण, पोरबंदर-वेरावल-दीव और द्वारका-ओखा-जामनगर—ये सभी 100 किलोमीटर के दायरे में धार्मिक, सांस्कृतिक और दर्शनीय स्थलों की तटीय सैर की पेशकश करते हैं।**

**• इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) ने बंदरगाहों, पर्यटन, नीति और तकनीकी विशेषज्ञों की एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की। राजीव जलोटा, सुशील**

**कुमार सिंह, कृष्णराज आर. और गौतम डे जैसे हितधारकों ने उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ मिलकर बंदरगाहों की तैयारी, आव्रजन प्रोटोकॉल, क्रूज टर्मिनल ढांचे, कौशल विकास और राज्य क्रूज नीति पर काम किया।**

**Key Points:-**

(i) GMB के CEO राजकुमार बेनीवाल और गुजरात पर्यटन के MD सैदिंगपुई छकछुआक ने प्रमुख बंदरगाहों पर 'क्रूज़-रेडी' गंतव्यों और तटीय भ्रमणों के विकास की योजनाओं का अनावरण किया। राज्य ने क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए घोघा-हजीरा रो-पैक्स फेरी सेवा पर भी प्रकाश डाला।

(ii) गुजरात की भागीदारी क्रूज़ भारत मिशन के व्यापक रोडमैप के अनुरूप अपनी पहली क्रूज़ पर्यटन नीति के शुभारंभ का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य 2029 तक समुद्री क्रूज़ यातायात को दस गुना बढ़ाना और भारत को शीर्ष वैश्विक क्रूज़ गंतव्यों में स्थान दिलाना है।

(iii) गुजरात में क्रूज़ सर्किट स्थापित करके, राज्य अन्य तटीय क्षेत्रों के लिए एक मज़बूत मिसाल कायम कर रहा है। यह व्यापक रणनीति सतत समुद्री विकास को संस्कृति-आधारित पर्यटन के साथ जोड़ती है, जिससे रोज़गार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा और भारत की नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

## 5. भारतीय नौसेना और BEL ने AI-सक्षम राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना (NMDA) के लिए समझौता किया

8 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (NMDA) परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य भारत की समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डेटा एकीकरण और वास्तविक समय के खतरों की निगरानी के माध्यम से सशक्त बनाना है।

- **यह समझौता उप नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती और BEL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ। यह साझेदारी भारतीय नौसेना की एक एकीकृत और बुद्धिमान समुद्री सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।**

- **NMDA परियोजना मौजूदा नेशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस (NC3I) नेटवर्क को AI-सक्षम NMDA नेटवर्क में अपग्रेड करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह प्रणाली विभिन्न समुद्री हितधारकों के बीच केंद्रीयकृत, वास्तविक समय में डेटा साझा करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएगी।**

- **हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC), जो वर्तमान में NC3I नेटवर्क का नोडल केंद्र है, को एक बहु-एजेंसी NMDA केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय**

**एजेंसियों के प्रतिनिधियों को एकीकृत किया जाएगा ताकि खतरों के लिए तालमेल से प्रतिक्रिया दी जा सके।**

**Key Points:-**

(i) NMDA परियोजना को "टर्नकी आधार" पर कार्यान्वित किया जाएगा और इसका प्रशासन भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और प्रमुख द्वीप क्षेत्रों को कवर करेगी ताकि भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और क्षेत्रीय जल पर व्यापक निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

(ii) इस प्रणाली में मछली पकड़ने, समुद्री परिवहन, पर्यावरण निगरानी और बचाव अभियानों जैसे क्षेत्रों से भी डेटा एकीकृत किया जाएगा। यह एक एकीकृत समुद्री खुफिया मंच के रूप में कार्य करेगा, जो समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरों की वास्तविक समय में पहचान और प्रतिक्रिया की क्षमता रखेगा।

(iii) यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भर रक्षा प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है और बहु-सेंसर डेटा फ्यूजन तथा AI-संचालित विश्लेषण के माध्यम से संचालनात्मक तत्परता को बेहतर बनाएगी। आईमैक, जो भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और BEL द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के तहत संयुक्त रूप से संचालित है, इस उन्नत निगरानी बुनियादी ढांचे का संचालन केंद्र होगा।

## INTERNATIONAL

### 1. यूरोपीय संघ की स्वीकृति मिलने के बाद बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां देश बन गया।

8 जुलाई, 2025 को, बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरोज़ोन में शामिल होने वाला 21वाँ देश बन गया, जब यूरोपीय संघ (EU) ने देश को यूरो (EUR) को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंज़ूरी दे दी। यह ऐतिहासिक कदम 1 जनवरी, 2026 से बुल्गारियाई लेव की जगह लेते हुए, मौद्रिक संघ में बुल्गारिया के पूर्ण एकीकरण का प्रतीक है।

- **यह अनुमोदन यूरोपीय संसद द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन पर आधारित था, जहां 531 यूरोपीय संसद सदस्यों (MEPs) ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, 69 ने इसके खिलाफ मतदान किया, और 79 ने मतदान में भाग नहीं लिया।**

- **इसके बाद यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने आधिकारिक रूपांतरण दर 1 यूरो = 1.95583 बल्गेरियाई लेव निर्धारित करके बुल्गारिया के प्रवेश की पुष्टि की। इस अंतिम अनुसमर्थन से मौद्रिक परिवर्तन के लिए यूरोपीय संघ के नियमों के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताएँ पूरी हो जाती हैं।**

- **यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि बुल्गारिया ने मास्ट्रिच अभिसरण मानदंडों के तहत सभी आर्थिक और विधायी आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिनमें मुद्रास्फीति नियंत्रण, सार्वजनिक ऋण स्थिरता, स्थिर विनिमय दरें और दीर्घकालिक ब्याज दर प्रदर्शन शामिल हैं। यूरो अपनाने को हरी झंडी देने से पहले इन आर्थिक संकेतकों की कई वर्षों तक निगरानी की गई।**

**Key Points:-**

(i) वर्तमान में 20 यूरोपीय देश यूरो का उपयोग करते हैं, और बुल्गारिया के शामिल होने के साथ, यह संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। लेन-देन की मात्रा और वैश्विक भंडार के हिसाब से यूरो दुनिया में दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। बुल्गारिया से पहले यूरोज़ोन में शामिल होने वाला आखिरी देश क्रोएशिया था, जिसने 1 जनवरी, 2023 को यूरो को अपनाया था।

(ii) यूरोज़ोन की सदस्यता जनवरी 2026 से शुरू होने वाले सभी सार्वजनिक और निजी लेन-देन में बुल्गारिया की राष्ट्रीय मुद्रा लेव के स्थान पर यूरो का उपयोग करेगी। इसमें सभी बैंकिंग, कॉर्पोरेट, निवेश और वाणिज्यिक वित्तीय संचालन शामिल होंगे। इस परिवर्तन से निवेशकों का विश्वास उल्लेखनीय रूप से बढ़ने, यूरोपीय संघ के भीतर व्यापार में वृद्धि और व्यापक आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

(iii) यूरो अपनाने के लिए, किसी देश को मास्ट्रिच संधि द्वारा निर्धारित कड़े मानदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें मुद्रास्फीति को तीन सबसे निचले यूरोपीय संघ के देशों के 1.5% के भीतर बनाए रखना, बजट घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% से नीचे सीमित रखना, विनिमय दर तंत्र II (ERM II) में बिना किसी अवमूल्यन के दो वर्षों तक भाग लेना, और दीर्घकालिक ब्याज दरों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सदस्यों के 2% के भीतर रखना शामिल है। बुल्गारिया द्वारा इन सभी का सफलतापूर्वक पालन इस मुद्रा परिवर्तन के लिए एक स्थिर आधार सुनिश्चित करता है।

## 2. नोवार्टिस को नवजात शिशुओं और छोटे शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा के लिए मंजूरी मिली।

स्विट्जरलैंड के औषधि प्राधिकरण स्विसमेडिक ने कोआर्टेम बेबी (जिसे रियामेट बेबी भी कहा जाता है) को मंजूरी दे दी है, जो दुनिया का पहला मलेरिया उपचार है, जो विशेष रूप से नवजात शिशुओं और 2-5 किलोग्राम वजन वाले छोटे शिशुओं के लिए तैयार किया गया है।

- **यह उपलब्धि मलेरिया देखभाल में उपचार संबंधी महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करती है, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में, जहां मलेरिया से संबंधित मौतों में 75% से अधिक मौतें पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की होती हैं।**

- **कोर्टेम बेबी में मलेरिया रोधी औषधियों आर्टीमीथर और ल्यूमेफैंट्रिन को चेरी के स्वाद के साथ सावधानीपूर्वक समायोजित कम खुराक वाले फॉर्मूलेशन में मिलाया गया है और इसे आसानी से लेने के लिए स्तन के दूध में घुलनशील बनाया गया है।**

- **इससे पहले, शिशुओं का इलाज वयस्कों या बड़े बच्चों वाली खुराक से किया जाता था, जिससे ओवरडोज या विषाक्तता का खतरा रहता था - इस अनुकूलित संस्करण में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है।**

**Key Points:-**

(i) इस मंज़ूरी से उम्मीद है कि स्विसमेडिक के विशेष वैश्विक स्वास्थ्य उत्पाद मार्ग की बदौलत नाइजीरिया,

केन्या और तंजानिया सहित कम से कम आठ मलेरिया-ग्रस्त अफ़्रीकी देशों में इसका तेज़ी से प्रसार होगा। नोवार्टिस की योजना इस उपचार को मुख्यतः गैर-लाभकारी आधार पर शुरू करने की है, जहाँ जन स्वास्थ्य समर्थक किफ़ायती और पारदर्शी मूल्य निर्धारण की आवश्यकता पर ज़ोर दे रहे हैं।

(ii) विशेषज्ञ इसे शिशु मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में एक क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन की डॉ. भार्गवी राव का कहना है कि यह उपचार में "लगभग 20 साल के अंतराल" को भरता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 में मलेरिया से होने वाली 5,97,000 मौतों की सूचना दी है—जिनमें से 95% अफ्रीका में होंगी, और छोटे बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित होंगे।

(iii) यह अनुमोदन मलेरिया-रोधी प्रतिरोध में वृद्धि और वैश्विक स्वास्थ्य निधि में बजट कटौती के बीच आया है, जो इसके महत्व को और अधिक रेखांकित करता है।

## BANKING & FINANCE

### 1. CCI ने केदारा कैपिटल और 360 वन द्वारा पोर्टर और UBS इंडिया इकाइयों में निवेश को मंजूरी दी।

8 जुलाई, 2025 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दो बड़े निवेशों को मंज़ूरी दे दी—निजी इक्विटी फर्म केदारा कैपिटल द्वारा लॉजिस्टिक्स यूनिकॉर्न पोर्टर में निवेश, और 360ONE ग्रुप द्वारा वैश्विक बैंक UBS AG से चुनिंदा वेल्थ और लेंडिंग यूनिट्स का अधिग्रहण। ये मंज़ूरियाँ भारत के लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

- **केदारा कैपिटल को अपने सहयोगी केदारा सैफायर होल्डिंग और केदारा कैपिटल फंड IV एआईएफ के माध्यम से पोर्टर की मूल कंपनी स्मार्टशिफ्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में अज्ञात इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए CCI की मंजूरी मिल गई है।**

- **यह सौदा पोर्टर के USD200 मिलियन सीरीज एफ फंडरेजिंग के बाद हुआ है, जिसका मूल्य मई 2025 में USD1.2 बिलियन है, जो इसे भारत के सबसे तेजी से बढ़ते यूनिकॉर्न में स्थान देता है और केदारा के लॉजिस्टिक्स टेक स्पेस में प्रवेश को चिह्नित करता है।**

**Key Points:-**

(i) वित्तीय क्षेत्र में, 360वन पोर्टफोलियो मैनेजर्स लिमिटेड, 360वन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड और 360वन प्राइम लिमिटेड को UBS इंडिया से पोर्टफोलियो प्रबंधन, स्टॉकब्रोकिंग, वित्तीय उत्पाद वितरण और ऋण पोर्टफोलियो सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के लिए CCI से हरी झंडी मिल गई।

(ii) इसके अतिरिक्त, UBS AG 360वन WAM लिमिटेड में 4.95% इक्विटी हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाले वारंट की सदस्यता लेगा, जो एक रणनीतिक दीर्घकालिक साझेदारी का संकेत है।

(iii) ये अनुमोदन भारतीय उद्योग के दो प्रमुख आख्यानों का समर्थन करते हैं: पोर्टर शहरों में अपने तकनीक-सक्षम लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म का निर्माण करने और परिचालन को मजबूत करने के लिए ताजा पूंजी का लाभ उठाएगा; 360ONE द्वारा UBS की संपत्ति और उधार देने वाली शाखाओं का अधिग्रहण

परिसंपत्ति प्रबंधन, ब्रोकिंग और क्रेडिट उत्पादों में इसकी पेशकश को बढ़ाता है, और HNI और खुदरा वित्तीय सेवा बाजार में इसकी स्थिति को मजबूत करता है।

## 2. केंद्र ने BIND योजना के तहत उज्जैन में नए आकाशवाणी केंद्र को मंजूरी दी।

8 जुलाई, 2025 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नया ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) केंद्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

- **इस निर्णय का उद्देश्य 2028 सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले क्षेत्र में मीडिया की पहुंच को मजबूत करना, समय पर सूचना प्रसार और सार्वजनिक संचार को बढ़ाना है।**

- **यह घोषणा नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की गई, जिसमें सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।**

- **ग्रामीण विकास की कहानियों को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और क्षेत्रीय प्रसारण बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन का लाभ उठाने पर चर्चा केंद्रित थी।**

**Key Points:-**

(i) स्वीकृति मिलने के बाद, उज्जैन में जल्द ही एक अत्याधुनिक स्टूडियो विकसित किया जाएगा, जिसका अंतरिम प्रसारण आकाशवाणी के मौजूदा इंदौर केंद्र द्वारा निर्माण पूरा होने तक प्रबंधित किया जाएगा। सीएम यादव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिंहस्थ मेले जैसे आयोजनों के दौरान समय पर सूचना देने और अंतिम छोर तक संचार को मज़बूत करने के लिए यह नया स्टूडियो बेहद महत्वपूर्ण है।

(ii) इस केंद्र को ₹2,539.61 करोड़ की BIND योजना के तहत वित्तपोषित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 2025-26 तक आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए प्रसारण अवसंरचना, डिजिटल स्टूडियो उन्नयन, सामग्री विकास और नागरिक कार्यों को बढ़ाना है। इस योजना का लक्ष्य एफएम की पहुँच में सुधार करना है—भौगोलिक रूप से 59% से 66% और जनसंख्या के आधार पर 68% से 80% तक विस्तार करना। यह दूरस्थ, वामपंथी उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए डीटीएच कवरेज का भी समर्थन करता है।

(iii) केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ने वंचित और आकांक्षी जिलों में मज़बूत प्रसारण नेटवर्क स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस पहल से प्रसारण उपकरण निर्माण, सामग्री उत्पादन और स्थापना सेवाओं में अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ई-लर्निंग और डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा देता है—ये सभी 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

# ECONOMY & BUSINESS

## 1. यामाहा मोटर ने अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर नया लोगो जारी किया।

जुलाई 2025 में, जापानी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड अपनी 70वीं स्थापना वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक नए डिज़ाइन वाले कॉर्पोरेट लोगो का अनावरण करेगी। यह घोषणा यामाहा मोटर के अध्यक्ष मोटोफुमी शितारा ने 1955 में अपनी स्थापना के बाद से कंपनी की विरासत के उत्सव के एक हिस्से के रूप में की।

**• यह 27 वर्षों में यामाहा के कॉर्पोरेट लोगो का पहला बड़ा नया डिज़ाइन है। यह नई पहचान, मोबिलिटी उद्योग में डिजिटल नवाचार, ग्राहक जुड़ाव और स्थिरता-संचालित प्रौद्योगिकी नेतृत्व की दिशा में यामाहा के रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है।**

**• अद्यतन लोगो में क्लासिक "ट्यूनिंग फोर्क" प्रतीक का एक सपाट द्वि-आयामी (2D) संस्करण शामिल है, जो इसे डिजिटल इंटरफेस के साथ अधिक सुसंगत बनाता है और वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्मों पर ब्रांड पहचान को बढ़ाता है।**

**• यामाहा ने अपनी 70वीं वर्षगांठ के लोगो के मूल विषय के रूप में "हर चीज़ एक चुनौती से शुरू होती है" की अवधारणा को अपनाया है। इस डिज़ाइन की प्रेरणा पहली यामाहा मोटरबाइक की लाइसेंस प्लेट से ली गई है, जो मोटर इंजीनियरिंग और खेलों में चुनौतियों का सामना करने की यामाहा की विरासत पर ज़ोर देती है।**

**Key Points:-**

(i) नए ब्रांड के लोगो में त्रिकोणीय व्यवस्था में जुड़े तीन ट्यूनिंग फोर्क शामिल हैं—यह प्रतीक संगीत वाद्ययंत्र निर्माण में यामाहा की जड़ों से गहराई से जुड़ा है। यह अब यामाहा के एक नवाचार-संचालित कंपनी के रूप में विकास का प्रतिनिधित्व करता है जो इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, उत्पादन और वैश्विक गतिशीलता में संतुलन बनाए रखती है।

(ii) इस परिवर्तन के साथ, यामाहा का लक्ष्य दोपहिया, समुद्री और रोबोटिक्स क्षेत्रों में उत्पाद उत्कृष्टता और वैश्विक नेतृत्व के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है।

(iii) इस रीब्रांडिंग से 2026 और उसके बाद के लिए योजनाबद्ध आगामी डिजिटल और इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च से पहले यामाहा की बाजार छवि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

## IMPORTANT DAYS

### 1. भारत 10 जुलाई 2025 को 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाएगा।

भारत ने 10 जुलाई 2025 को 25वां राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस (National Fish Farmers Day – NFFD) मनाया। इस दिन का उद्देश्य मत्स्य पालन, जलकृषि विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों के योगदान को सम्मानित करना और टिकाऊ जलकृषि

(sustainable aquaculture) को बढ़ावा देना है। इस आयोजन से भारत के ब्लू इकोनॉमी सेक्टर में योगदान देने वाले लाखों किसानों को सराहा गया।

**• राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी, जब भारत सरकार (Government of India – GoI) ने हर साल 10 जुलाई को इस दिन को मनाने की घोषणा की। यह दिवस वैज्ञानिक जलकृषि (scientific aquaculture) को बढ़ावा देने और समुद्री व अंतर्देशीय मत्स्य पालन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, ताकि खाद्य सुरक्षा और आजीविका को सशक्त किया जा सके।**

**• 2025 का संस्करण ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय मीठाजल जलकृषि संस्थान (ICAR-Central Institute of Freshwater Aquaculture – ICAR-CIFA) में आयोजित किया गया। यह आयोजन मत्स्य पालन विभाग (Department of Fisheries – DoF) द्वारा आयोजित किया गया, जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying – MoFAH&D) के अंतर्गत कार्य करता है।**

**Key Points:-**

(i) इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की, जो MoFAH&D और पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj – MoPR) में मंत्री हैं। उन्होंने मत्स्य उत्पादकता को दोगुना करने, मूल्य वर्धित मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) के तहत किसानों को लाभ देने की प्रतिबद्धता जताई।

(ii) कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एस. पी. सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार तकनीकी नवाचारों और हैचरी विकास (hatchery development) ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र को बदल दिया है और देशभर के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाया है।

(iii) कार्यक्रम के दौरान NFFD की सिल्वर जुबली को चिह्नित किया गया, जिसमें तकनीकी सत्र, प्रदर्शनी, सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालकों को पुरस्कार, और जलवायु-लचीली जलकृषि (climate-resilient aquaculture), एआई-सक्षम निगरानी प्रणाली और तालाब उत्पादकता सुधार पर नीति चर्चा आयोजित की गई। देशभर से आए सफल मत्स्य पालकों ने अपनी कहानियां साझा कीं और ICAR-CIFA ने अपने नवीन अनुसंधान कार्यों को प्रस्तुत किया।

## SCIENCE AND TECHNOLOGY

### 1. भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत 'INS निस्तार' कमीशन किया।

जुलाई 2025 में, रक्षा मंत्रालय (MoD) के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना (INS) को भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) 'INS निस्तार' सौंपा। यह पोत भारत की गहरे समुद्र में बचाव और गोताखोरी क्षमताओं को बढ़ाता है और नौसेना के बुनियादी ढाँचे में आत्मनिर्भरता के राष्ट्र के लक्ष्य का समर्थन करता है।

**• यह जहाज भारतीय नौवहन रजिस्टर (IRS) के नियमों के अनुसार वर्गीकृत और निर्मित है। इसका नाम 'निस्तार' रखा गया है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मुक्ति या बचाव।**

**• यह युद्धपोत गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्यों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है और यह 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए भारत की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है।**

**• INS निस्तार अत्याधुनिक डीप डाइविंग उपकरणों से सुसज्जित है और इसकी विस्थापन क्षमता 10,000 टन है। इसकी लंबाई 118 मीटर है और यह 300 मीटर तक गहरे समुद्र में संतृप्ति डाइविंग मिशन करने में सक्षम है। इस पोत में 75 मीटर की गहराई तक संचालन के लिए एक साइड डाइविंग स्टेज भी है, जो पानी के भीतर लचीली क्षमताएँ सुनिश्चित करता है।**

**Key Points:-**

(i) इस जहाज को गहरे जलमग्न बचाव पोत (DSRV) के लिए 'मदर शिप' के रूप में भी डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह पनडुब्बी बचाव अभियानों को अंजाम दे सकता है। आपात स्थिति में, यह निष्क्रिय पनडुब्बियों से चालक दल को बचा सकता है, जो पानी के भीतर नौसैनिक अभियानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है।

(ii) INS निस्तार उन्नत रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (ROVs) से सुसज्जित है और 1,000 मीटर तक की गहराई पर पानी के भीतर के कार्यों को संभाल सकता है। यह इसे न केवल भारतीय नौसेना के पनडुब्बी बेड़े के लिए, बल्कि समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया अभियानों के लिए भी एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है।

(iii) उल्लेखनीय है कि INS निस्तार में 75% से अधिक उपकरण और पुर्जे घरेलू विक्रेताओं से प्राप्त किए गए हैं, जिससे यह अपनी श्रेणी में सबसे अधिक स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफार्मों में से एक बन गया है। यह भारत के रणनीतिक रक्षा दृष्टिकोण के अनुरूप है और देश के रक्षा जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।

## 2. भारतीय नौसेना ने स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट 'ERASR' का सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया।

जुलाई 2025 में, भारतीय नौसेना (IN) ने भारतीय नौसेना पोत (INS) कवरत्ती से स्वदेशी रूप से विकसित अंतर्जलीय युद्ध हथियार प्रणाली, विस्तारित दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट (ERASR) के उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। ये परीक्षण भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और पनडुब्बी रोधी युद्ध में तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।

**• ERASR प्रणाली एक पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है जिसे विशेष रूप से दुश्मन की पनडुब्बियों द्वारा उत्पन्न पानी के भीतर के खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस हथियार को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर (IRL) प्रणालियों से प्रक्षेपित किया जाता है और इसे उच्च-प्रदर्शन वाले पानी के भीतर युद्ध समर्थन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**

**• ERASR में दो-रॉकेट मोटर विन्यास है, जो इसे सटीकता और विश्वसनीयता के साथ लंबी दूरी तक**

**उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। इस प्रणाली में घरेलू स्तर पर विकसित इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज (ETF) भी शामिल है, जो विभिन्न समुद्री परिस्थितियों में सटीकता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।**

**Key Points:-**

(i) उपयोगकर्ता परीक्षणों के दौरान, कुल 17 ERASR रॉकेट विभिन्न स्थानों पर दागे गए। इन परीक्षणों ने वारहेड की रेंज क्षमता, फ्यूज़ तकनीक और प्रदर्शन का सफलतापूर्वक सत्यापन किया। सभी मिशन उद्देश्य प्राप्त हुए, जिससे ERASR प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता और परिचालन तत्परता की पुष्टि हुई।

(ii) ERASR रॉकेट का डिज़ाइन और इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (ARDE) द्वारा किया गया है। ARDE, रक्षा मंत्रालय (MoD) के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) का एक अंग है। उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला (HEMRL) और नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL) द्वारा सहयोगात्मक विकास सहायता प्रदान की गई।

(iii) ERASR का उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) सहित प्रमुख भारतीय रक्षा निर्माताओं द्वारा किया जाएगा। यह भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाकर और समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करके 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

## OBITUARY

### 1. ब्रिटेन के पूर्व कैबिनेट मंत्री नॉर्मन टेबिट का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

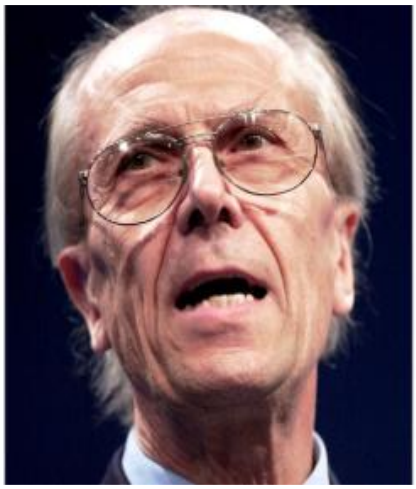

7 जुलाई, 2025 को, मुखर कंज़र्वेटिव राजनेता और मार्गरिट थैचर के प्रमुख सहयोगी लॉर्ड नॉर्मन टेबिट का बरी सेंट एडमंड्स, सफ़ोक स्थित अपने घर पर शांतिपूर्वक निधन हो गया। 94 वर्ष की आयु में उनका निधन उनके दृढ़ विश्वास, नाटकीय सुधारों और व्यक्तिगत लचीलेपन से भरे राजनीतिक जीवन का अंत है।

- **टेबिट का संसदीय करियर 1970 से 1992 तक रहा, पहले वे एपिंग और बाद में चिंगफोर्ड से सांसद रहे, उसके बाद 1992 में उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पदोन्नत किया गया, आधिकारिक तौर पर वे 2022 में सेवानिवृत्त होंगे।**

- **मार्गरिट थैचर के मंत्रिमंडल में, उन्होंने कई उच्च-स्तरीय भूमिकाएँ निभाईं: रोजगार सचिव (1981-83), व्यापार और उद्योग सचिव (1983-85), डची ऑफ लैंकेस्टर के चांसलर और कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष (1985-87)।**

- **उन्होंने थैचर-युग के आर्थिक एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 1982 के रोजगार अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियनों की शक्ति पर अंकुश लगाने, असफल उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करने और ब्रिटेन में मुक्त बाज़ार की नीति को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन किया। बेरोज़गारी पर बहस के दौरान उनकी प्रसिद्ध "अपनी बाइक पर चढ़ो"**

**टिप्पणी उनके लचीलेपन और आत्मनिर्भरता के दर्शन को दर्शाती थी।**

**Key Points:-**

(i) टेबिट 1984 में ब्राइटन ग्रैंड होटल में हुए IRA बम विस्फोट में बच गए थे, जहाँ उन्हें और उनकी पत्नी मार्गरिट को गंभीर चोटें आईं—उनकी पत्नी हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गईं और उन्हें हमले की शारीरिक निशानियाँ जीवन भर याद रहीं। उन्होंने 1987 में अपनी पत्नी की देखभाल के लिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और 2020 में उनके निधन तक खुद को उनकी भलाई के लिए समर्पित कर दिया।

(ii) सेवानिवृत्ति के बावजूद, टेबिट एक आजीवन सहकर्मी के रूप में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, उन्होंने मजबूत यूरोसेप्टिक विचारों को व्यक्त किया - विशेष रूप से मास्ट्रिच संधि का विरोध किया - और अपने बाद के वर्षों में रूढ़िवादी सिद्धांतों की वकालत की।

(iii) प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने टेबिट के स्थायी प्रभाव की प्रशंसा की, जबकि कंजर्वेटिव नेता केमी बेडेनोच ने उन्हें "कंजर्वेटिव राजनीति का दिग्गज" कहा।

## Static GK

| | | |
|---|---|---|
| **Ministry of Information & Broadcasting (MIB)** | मंत्री: अश्विनी वैष्णव | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **Central Electricity Authority (CEA)** | अध्यक्ष : घनश्याम प्रसाद | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **Bulgaria** | प्रधानमंत्री (PM) : रोसेन दिमित्रोव ज़ेलियाज़कोव | राजधानी : सोफिया |
| **CCI** | अध्यक्ष: रवनीत कौर | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **Hindustan Shipyard Limited (HSL)** | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD): कमोडोर हेमंत खत्री (सेवानिवृत्त) | मुख्यालय: विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश |
| **Gujrat** | मुख्यमंत्री: भूपेन्द्र पटेल | राज्यपाल: आचार्य देवव्रत |
| **Bharat Electronics Limited (BEL)** | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) : मनोज जैन | मुख्यालय : बेंगलुरु, कर्नाटक |